as fifteen memebrs have considered it and then they have given these recommendations...*(Interruptions)*... As I have been saying right from the day we came...*(Interruptions)*... We are very serious about it.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: After all, lakhs of people of Delhi are worried about it...*(Interruptions)*... Sir, they have already assured us many times. आखिर जो भी करना चाहते है करिए और अमेंडमेंट इस सेशन में तो करिए।

MR. CHAIRMAN: If you want, you can ask a supplementary....*(Interruptions)*... But, unfortunately, the Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

गरीबों के लिए विकास योजना

*105. **श्री राधवजी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनायी है जहां तीस से लेकर चालीस प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-ज्ञापन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश और असम को उपरोक्त योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन-किन योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ग) किसी राज्य का विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है, बहरहाल, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) प्रमुख केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं। नेहरू रोजगार योजना (एन०आर० वाई०) प्रमुख शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। विशेष रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईडीपी), जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके अलावा, सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करती है, जिसमे लोगों की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक विकास घटकों को पर्याप्त आवंटन के प्रावधान पर जोर दिया गया है। इनमें से सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की पहचान की गई है ताकि उन्हें समयबद्ध ढंग से कवर किया जा सके। इसके लिए, इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं हेतु राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रुप में बजट में 2466 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। यह परिव्यय इन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों की योजनाओं में निर्धारित परिव्ययों से अलग होगा।

Growth Rate of Unemployment

*106. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state the rate of growth of unemployment and placement during the Eighth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER ALAGH): Annual rate of growth of unemployment based on Usual Principal Status (UPS) as estimated from the quinquennial serveys of NSSO conducted during 1987-88 and 1993-94 is (−) 4.16%, while the employment growth during the same period is 2.23%. However the current Daily Status Unemployment of male workers which is a measure of the utilization of labour time has gone up from, 5.54 percent to 5.91 percent in the same period and this is a matter of concern. The rural male worker current daily status unemployment rate for male workers has also gone up from 4.58 percent to 5.64 percent.